कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री एस0आर0 बालासुब्रहमण्यन**) : (क) से (घ) बहुत सी राज्य सरकारों, यथा मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा तथा राजस्थान की राज्य सरकारों ने यह रिपोर्ट किया हैं कि वे जनता को एक या अधिक क्षेत्रों से संबंधित सरकार की कार्रवाई और रैका ई संबंधी सूचना तक आबाध और आसान पहुंच मुहैया करवा रही हैं। मध्य प्रदेश के संबंध में यह रिपोर्ट किया गया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपस्थिति-नामावली (मस्टर-रोल) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की सूची, भूमि-रैकॉर्ड तथा प्रदूषण-नियंत्रण बोर्ड जैसे क्षेत्रों में पारदर्शिता संबंधी अनुदेश लागू कर दिए गए हैं। केन्द्र सरकार ने सभी मंत्रालयों/विभागों को पारदर्शिता के बारे में तथा अवर्गीकृत सूचना तक पहुंच के संबंध में अनुदेश जारी कर दिए हैं। इसने (केन्द्र सरकार ने) इस प्रयोजन से दिल्ली में, जनता से परस्पर विचारशीलता, क्रियाशीलता और प्रभावशीलता वाले चुनिन्दा विभागों से सूचना और सुविधा-काउंटर खोलने के लिए भी कहा हैं।

Indian Offer of Inspection of Chemical Weapons

36. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item which appeared in the Times of India (New Delhi) dated the 27th June, 1997 under the caption "India throws open chemical weapons stocks for inspection"; if so, Government's reaction thereto;

(b) whether Government have taken enough safeguards to ensure that country's security is not compromised; and

(c) if so, the details thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) Yes, Sir. India is an original State Party to the Chemicals Weapons Convention which entered into force on 29th April, 1997. The convention requires States Parties to provide certain declarations within stipulated time schedules. India's declarations were made in keeping with the treaty obligations.

(b) and (c) India considers the CWC to be a model disarmament agreement and has asked the countries, that have not yet done so, to complete their ratification proceedings, in order to make the CWC genuinely universal and comprehensive. To date 95 countries, inclduing the USA and China have ratified this Treaty. Government remains fully committed to taking the necessary steps to safeguard India's security and national interest against all eventualities and Government's decision is in keeping with its commitments.

पड़ोसी देशों के संबंध मधुर बनाने हेतु वार्ता

*37. **प्रो0 राम बख्श सिंह वर्मा** : क्या प्रावधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान सरकार ने पड़ोसी देशों से अपने संबंध बनाने के लिए कोई वार्ता की हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) पड़ोसी देशों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री सलीम इकबाल शेरवानी**) : (क) से (ग) पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने के लिए बातचीत का देश-वार ब्यौरा नीचे दिए अनुसार हैं:-

पाकिस्तान:

सरकार पाकिस्तान के साथ विश्वास, मित्रता और सहयोग के संबंध में स्थापित करने की इच्छुक हैं और द्विपक्षीय बातचीत की प्रक्रिया के माध्यम से बकाया मसलों को शन्तिपूर्ण ढंग से हल करना चाहती हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री देव गौड़ा ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को भेजे गए अपने बधाई पत्र में पारस्परिक हितचिंता के मुद्दों पर उपयुक्त स्तर पर दोनों देशों के बीच व्यापक बातचीत करने का प्रस्ताव रखा था । इस पहल के परिणाम-स्वरूप नई दिल्ली में 28 से 31 मार्च, 1997 तक विदेश सचिव स्तर की बातचीत पुनः आरंभ हुई। माले में सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधान मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने 12 मई, 1997 को द्विपक्षीय बातचीत के लिए पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ